

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 388क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

प्रश्नावली

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यान्वित संवैधानिक संरक्षोपायों, कल्याण और विकास योजनाओं की समीक्षा

2026

बी-विंग, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली- 110003

वेबसाइट: <https://ncst.nic.in> | अनुसूचित जनजाति के लिए शिकायत पोर्टल <https://ncstgrams.gov.in>

विषय - वस्तु

- क. सामान्य.....
- ख. जनसांख्यिकी.....
1. जनसंख्या विवरण (नवीनतम जनगणना के अनुसार).....
 2. अनुसूचित जनजाति बस्तियाँ.....
 3. साक्षरता दर (नवीनतम जनगणना के अनुसार).....
 4. आर्थिक स्थिति.....
- ग. पोषण और स्वास्थ्य.....
5. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य.....
 6. पोषण (अभी तक).....
 7. स्वास्थ्य अवसंरचना.....
- घ. अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान.....
8. अनुसूचित जण जाति घटक (एसटीसी) (जिसे इससे पूर्व जनजातीय उप-योजना कहा जाता था।).....
 9. संविधान का अनुच्छेद 275 (1) (अनुसूचित जण जाति हेतु अनुदान).....
- ङ. भारत सरकार की योजनाएं.....
10. अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमुख योजनाएँ.....
 - क. धरती आबा जंजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयू).....
- च. शिक्षा.....
11. मूलभूत शिक्षा विवरण.....
 - क) विद्यालय अवसंरचना.....
 - ख) सकल भर्ती अनुपात (जी ई आर) (पिछले तीन वर्षों में).....
 12. शिक्षक- छात्र अनुपात और शिक्षक की रिक्ति.....
 13. व्यावसायिक (केंद्रीय/राष्ट्रीय के अलावा) संस्थान में अनुसूचित जण जातियों के लिए आरक्षित सीटें (राष्ट्रीय के अलावा/केन्द्रीय).....
 14. अनुशिक्षण और प्रशिक्षण.....
- छ. जनजातीय/सामाजिक कल्याण.....
15. राज्य सरकार द्वारा चालित छात्रावास (आज तक).....
 16. छात्रवृत्ति (पिछले तीन वर्षों में).....
- ज. कौशल विकास और रोजगार.....
- क. कौशल.....
- झ. वन अधिकार एवं संबंधित जानकारी.....
17. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, / (2006 वन अधिकार अधिनियम (एफ़आरए).....
 - ग) लघु वन उपज.....
 - घ) कृषि.....
 - ङ) सिंचाई.....
 - च) पशुपालन.....
 - छ) मत्स्य पालन.....

- ज. वित्तीय समावेशन और आजीविका.....
18. बैंकिंग.....
 19. क्रेडिट.....
 20. आजीविका आज की स्थिति के अनुसार.....
- ट. आवास और अवसंरचना.....
21. प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी).....
 22. जल आपूर्ति.....
 23. स्वच्छता.....
 24. सड़कें (पीएमजीएसवाई).....
- ठ. अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षा उपाय, सेवा मामले और कानूनी तंत्र.....
25. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989/ पीओए अधिनियम, 1989.....
 26. पंचायती राज संस्थान से संबंधित.....
 27. सेवा सुरक्षा उपाय.....
 - ii. जाति प्रमाण पत्र/अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक दावों का सत्यापन.....
 - iii. नौकरीपेशा लोगों के लिए.....
- ड. शासन और कार्यान्वयन तंत्र.....
28. जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी).....
 29. प्रमुख परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण/भूमि आवंटन एवं हस्तांतरण.....
 30. प्रमुख परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण – भूमि अधिग्रहण में पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013.....
 31. राज्य में जनजातीय अनुसंधान संस्थान.....
- ढ. छठी अनुसूची क्षेत्र राज्य से जानकारी.....
32. जिला परिषदें और क्षेत्रीय परिषदें.....

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम:

क. सामान्य

1. (क) राज्य और केंद्र शासित की सामान्य रूपरेखा

- i. राज्य में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों को देखने वाले नोडल विभाग का नाम और पता:
- ii. नोडल विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव का नाम और संपर्क विवरण:
 - क. नाम और पदनाम:
 - ख. पता:
 - ग. दूरभाष और फ़ैक्स सं.:
 - घ. मोबाइल नंबर:
 - ङ. ई-मेल आईडी:
- iii. एनसीएसटी को सूचना भेजने के लिए नोडल अधिकारी/संपर्क अधिकारी के रूप में नामित अधिकारी का संपर्क विवरण:
 - क. नाम और पदनाम:
 - ख. पता:
 - ग. दूरभाष और फ़ैक्स सं.:
 - घ. मोबाइल नंबर:
 - ङ. ई-मेल आईडी:
- iv. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई पिछली समीक्षा की तिथि:
- v. दिनांक..... को भेजी गई एनसीएसटी की सिफ़ारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (कृपया प्रति संलग्न करें):
- vi. क्या राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है?
 - क. यदि हाँ, तो क्षेत्र विवरण सहित आईटीडीपी/आईटीडीए, एमएडीए तथा क्लस्टरों की जिलावार संख्या
- vii. 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाली बस्तियों की संख्या-
- viii. राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को स्पष्टतः दर्शाने वाला मानचित्र
- ix. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कुल जिलों की संख्या-
 - क. राज्य में आकांक्षी जिलों की संख्या-
 - ख. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में ब्लॉकों की कुल संख्या-
 - ग. राज्य में आकांक्षी ब्लॉकों की संख्या-
 - घ. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों की कुल संख्या-
 - ङ. नगरपालिका/नगरनिगम/नगर परिषद की संख्या-

ख. जनसांख्यिकी

1. जनसंख्या वितरण (नवीनतम जनगणना के अनुसार)

श्रेणी	कुल जनसंख्या (लाखों में)	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (लाखों में)	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत
कुल जनसंख्या			

ग्रामीण जनसंख्या			
शहरी जनसंख्या			
पुरुष			
महिला			

2. अनुसूचित जनजाति बस्तियाँ

- i. राज्य में सभी अनुसूचित जनजातियों की सूची अवरोही क्रम में समुदायवार जनसंख्या प्रस्तुत करें तथा उनके निवास क्षेत्रों के विवरण सहित प्रदान करें।

क्र. सं.	एसटी समुदाय का नाम	क्या विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी)	जनसंख्या	कुल एसटी जनसंख्या का प्रतिशत	निवास जिला

3. साक्षरता दर(नवीनतम जनगणना के अनुसार)

श्रेणी	कुल जनसंख्या में साक्षरता (%)		अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में साक्षरता(%)	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
कुल जनसंख्या				
ग्रामीण जनसंख्या				
शहरी जनसंख्या				

4. आर्थिक स्थिति

(दिनांक- _____ के _____) सर्वेक्षण के अनुसार)

	कुल जनसंख्या				अनुसूचित जनजाति जनसंख्या			
	कुल जनसंख्या	कुल परिवार	बीपीएल परिवारों की संख्या	कुल परिवारों में से बीपीएल परिवारों का प्रतिशत	कुल जनसंख्या	कुल परिवार	बीपीएल परिवारों की संख्या	कुल परिवारों में से बीपीएल परिवारों का प्रतिशत
कुल								
ग्रामीण								
शहरी								

ग. स्वास्थ्य और पोषण

5. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

क्र. सं.	विषय	राज्य का औसत	राज्य में एसटी
क.	संस्थागत प्रसव दर		
ख.	शिशु मृत्यु दर		
ग.	नवजात मृत्यु दर		
घ.	पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर		
ङ.	जन्म के समय लिंग अनुपात		
च.	5 वर्ष की आयु से कम के ऐसे बच्चे जिनका वजन कम है(%)		
छ.	6-59 महीने की आयु के बच्चे जो एनीमिया से ग्रस्त हैं		
ज.	मातृ मृत्यु अनुपात		
झ.	उन माताओं का (%) जिन्हें प्रसवपूर्व पूर्ण देखभाल सुविधा प्राप्त हुई		
ञ.	प्रसव के 2 दिनों के भीतर प्रसवोत्तर देखभाल प्राप्त करने वाली माताएं (%)		
ट.	15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की एनीमिया से पीड़ित महिलाएं (%)		

6. पोषण (आज तक)

i. राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र-

क्र. सं.	कुल आंगनबाड़ी केंद्र	ग्रामीण क्षेत्रों में एडबल्यूसी	शहरी क्षेत्र में एडबल्यूसी	स्वयं के भवन में स्थित एडबल्यूसी (कुल)	स्वयं के भवन में स्थित एडबल्यूसी - ग्रामीण	स्वयं के भवन में स्थित एडबल्यूसी - शहरी	अनुसूचित क्षेत्रों में एडबल्यूसी

ii. पंजीकरण का विवरण (अनुसूचित जनजाति लाभार्थी)

कुल एसटी लाभार्थी	0-3 वर्ष के बच्चे (एसटी)	3-6 वर्ष के बच्चे (एसटी)	गर्भवती महिलाएँ (एसटी)	स्तनपान कराने वाली माताएँ (एसटी)

iii. अनुसूचित जनजाति के बच्चों की पोषण स्थिति

गंभीर तीव्र कुपोषण एसएएम (अनुसूचित जनजाति)	मध्यम तीव्र कुपोषण एमएएम (अनुसूचित जनजाति)	सामान्य (अनुसूचित जनजाति)

iv. शारीरिक वृद्धि निगरानी कवरेज (अनुसूचित जनजाति)

मापी गई ऊँचाई (%)	मापा गया वजन (%)	अद्यतन शारीरिक वृद्धि निगरानी (हाँ/नहीं)

v. आईसीडीएस के अंतर्गत सेवा प्रदायगी (अनुसूचित जनजाति)

घरेलू राशन का वितरण (हाँ/नहीं/%)	पके भोजन का वितरण (हाँ/नहीं/%)

vi. आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज प्रसूति माता -

- क. कुल-
ख. एसटी-

7. स्वास्थ्य अवसंरचना

i. स्टाफ की स्थिति (पिछले वित्तीय वर्ष में, सभी राज्य के लिए)

प्रकार	संख्या	डॉक्टर			नर्स		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
जिला अस्पताल							
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)							
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)							
उप केंद्र							

प्रकार	संख्या	विशेषज्ञ			पारामेडिकल स्टाफ		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
जिला अस्पताल							
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)							
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)							
उप केंद्र							
अन्य							

ii. स्टाफ की स्थिति (पिछले वित्तीय वर्ष में, जनजाति क्षेत्रों के लिए)

प्रकार	संख्या	डॉक्टर			नर्स		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
जिला अस्पताल							
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)							
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)							
उप केंद्र							

प्रकार	संख्या	विशेषज्ञ	पैरामेडिकल स्टाफ
--------	--------	----------	------------------

	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
जिला अस्पताल						
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)						
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)						
उप केंद्र						
अन्य						

iii. राज्य में आयोजित कुल स्वास्थ्य शिविरों की संख्या (पिछले तीन वर्षों में) :

क. सिकल सेल एनीमिया (एससीए) जांच हेतु स्वास्थ्य शिविर -

ख. क्या राज्य में सिकल सेल एनीमिया के मामले हैं? यदि हाँ, तो उसकी जिलावार संख्या-

vii. राज्य में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी-

क. कुल:

ख. एसटी:

viii. राज्य में कार्यात्मक आयुष्मान आरोग्य मंदिर की संख्या-

ix. राज्य में ज़िले-वार जन औषधि केंद्रों की संख्या-

x. जनजातीय क्षेत्रों/ जनजातीय आबादी में व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम (खनन क्षेत्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं सहित) सहित कोई विशेष स्वास्थ्य समस्याएँ-

घ. अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान

8. अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) (जिसे इससे पूर्व जनजातीय उप-योजना कहा जाता था)

i. कृपया राज्य योजना से अनुसूचित जनजाति घटक (जिसे अनुसूचित जनजातियों हेतु विकास कार्ययोजना-डीएपीएसटी के रूप में भी; पूर्व में जनजातीय उप-योजना-टीएसपी के नाम से जाना जाता था) के अंतर्गत आवंटित निधि तथा पिछले तीन वर्षों में किए गए व्यय का विवरण प्रस्तुत करें।-

वर्ष	कुल राज्य योजना आवंटन	एसटीसी के तहत आवंटन	कुल आवंटन में एसटीसी का प्रतिशत	एसटीसी के तहत जारी	एसटीसी के तहत व्यय	एसटीसी के तहत व्यय का प्रतिशत

9. संविधान का अनुच्छेद 275(1) (अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु अनुदान)

i. कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्राप्त निधियों के परियोजना/योजना-वार उपयोग का विवरण प्रस्तुत करें।

वर्ष	परियोजना/योजना का नाम	आवंटित निधि (लाख रुपये में)	जारी निधि (लाखों में)	किया गया व्यय (लाखों में)	उपयोग की गई निधि %	टिप्पणी

ड. भारत सरकार की योजनाएँ

10. अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमुख योजनाएँ

क. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)

- i. योजना के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तिथि तक डीएजेजीयूए के कार्यान्वयन का विस्तृत विवरण प्रदान करें:

क्र. सं.	मंत्रालय	मध्यवर्तन (योजना)	लक्ष्य	लाभार्थी/मध्यवर्तन /उपलब्धि	अभिज्ञात कमियाँ	टिप्पणी
1	ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)	पक्के मकान (पीएमएवाई-जी) संपर्क सड़कें (पीएमजीएसवाई)				
2	जल शक्ति मंत्रालय	(i) जल जीवन मिशन – एफएचटीसी (ii) सामुदायिक जल नल				
3	विद्युत मंत्रालय	गृह विद्युतीकरण (आरडीएसएस)				
4	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	नई सौर ऊर्जा योजना (ऑफ-ग्रिड)				
5	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	मोबाइल मेडिकल यूनिट (एनएचएम) आयुष्मान कार्ड (पीएम-जेएवाई)				
6	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	एलपीजी कनेक्शन (पीएम उज्ज्वला योजना)				
7	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्र (पोषण अभियान)				
8	शिक्षा मंत्रालय	छात्रावास निर्माण (समग्र शिक्षा अभियान)				
9	आयुष मंत्रालय	पोषण वाटिकाएँ (राष्ट्रीय आयुष मिशन)				
10	दूरसंचार विभाग (डीओटी-एमओसी)	भारतनेट/यूएसओएफ कनेक्टिविटी				
11	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	कौशल भारत मिशन/कौशल केंद्र				
12	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय	डिजिटल पहलें				
13	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	सतत कृषि (विभिन्न योजनाएँ)				

क्र. सं.	मंत्रालय	मध्यवर्तन (योजना)	लक्ष्य	लाभार्थी/मध्यवर्तन /उपलब्धि	अभिज्ञात कमियाँ	टिप्पणी
14	मत्स्य पालन विभाग	मछली पालन सहायता (पीएमएमएसवाई)				
	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	पशुधन पालन (राष्ट्रीय पशुधन मिशन)				
15	पंचायती राज मंत्रालय	क्षमता निर्माण (आरजीएसए)				
16	पर्यटन मंत्रालय	जनजातीय होमस्टे (स्वदेश दर्शन)				
17	जनजातीय कार्य मंत्रालय	पीएमएएजीवाई/एससीए से टीएसपी				

ख. पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) *

[*चूँकि यह योजना विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए है, अतः राज्य में यदि कोई पीवीटीजी समुदाय विद्यमान हो, तभी कृपया जानकारी प्रदान की जाए।]

- क्या राज्य में प्रधानमंत्री-जनमन योजना लागू/कवर की गई है? यदि हाँ, तो अनुलग्नक में निम्नलिखित विस्तृत जानकारी अलग से प्रस्तुत करें।
- राज्य में चिन्हित पीवीटीजी बस्तियों की कुल संख्या और उनकी जिले-वार जनसंख्या-
- क्या सभी चिन्हित बस्तियों में आधारभूत सर्वेक्षण किए गए हैं? (हाँ/नहीं)

क. यदि हाँ, तो पूरा करने की तिथि:

- राज्य में निम्नलिखित योजनाओं/मध्यवर्तनों के संतृप्तिकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? (विवरण पृथक संलग्नक में प्रदान करें)।
- योजनावार प्रगति (दिनांक तक (दिनांक का उल्लेख करें)....)

क्र. सं.	घटक	लक्षित परिवार	कवर किए गए परिवार	अभिज्ञात कमियाँ	टिप्पणी
1.	पक्के मकानों का प्रावधान (पीएमएवाई-जी)				
2.	संपर्क सड़कें (पीएमजीएसवाई)				
3.	नल से जल आपूर्ति सामुदायिक जल आपूर्ति (जेजेएम)				
4.	दवा की लागत के साथ मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ				
5.	छात्रावासों का निर्माण और प्रचालन				
6.	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण और प्रचालन				
7.	वीडीवीके की स्थापना				
8.	बहुउद्देशीय केन्द्रों (एमपीसी) का निर्माण				
9.	<ul style="list-style-type: none"> अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण सड़कों और एमपीसी में सौर प्रकाश 				

क्र. सं.	घटक	लक्षित परिवार	कवर किए गए परिवार	अभिज्ञात कमियाँ	टिप्पणी
	<ul style="list-style-type: none"> 0.3 किलोवाट सौर ऑफ-ग्रिड सिस्टम का प्रावधान 				
10.	मोबाइल टावरों की स्थापना				
11.	व्यावसायिक शिक्षा और कौशल				

च. शिक्षा

11. बुनियादी शिक्षा विवरण-

i. जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा व्यय:स्रोत:.....

ii. विद्यालय का विवरण:

	प्राथमिक	सेकण्डरी	उच्चतर माध्यमिक	कुल
सरकारी विद्यालयों की संख्या				

विद्यार्थी						
प्रकार	स्वीकृत सीट		भरी गई सीट		रिक्त सीट	
	कुल	एसटी	कुल	एसटी	कुल	एसटी
प्राथमिक						
सेकण्डरी						
उच्चतर माध्यमिक						

शिक्षक						
संस्थान प्रकार	स्वीकृत पद		भरे गए पद		रिक्त पद	
	कुल	एसटी	कुल	एसटी	कुल	एसटी
प्राथमिक						
सेकण्डरी						
उच्चतर माध्यमिक						

क) विद्यालय की अवसंरचना

विषय	पृथक कार्यात्मक शौचालयों सहित		पृथक कार्यात्मक शौचालयों रहित	
	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ
विद्यालयों की संख्या				

विषय	आरओ मशीनों सहित	पेयजल सुविधा सहित (आरओ मशीन के अलावा)	पेयजल सुविधा रहित
विद्यालयों की संख्या			

विषय	कार्यात्मक बिजली सुविधा सहित	कार्यात्मक बिजली सुविधा रहित
विद्यालयों की संख्या		

- आरटीई द्वारा निर्दिष्ट छात्र-शिक्षक अनुपात का अनुपालन करने वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या-
- शैक्षणिक सत्र शुरू होने के एक महीने के भीतर बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत-
- स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने के लिए क्लस्टर स्तर की पहलों का विवरण-
- महिला कॉमन रूम वाले स्कूलों की संख्या-
- कंप्यूटर लैब/स्मार्ट-क्लासरूम वाले स्कूलों की संख्या-
- पुस्तकालय वाले विद्यालयों की संख्या-
- पारंपरिक जनजाति खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल की जानकारी -
(कृपया ऊपर दी गई जानकारी का स्रोत भी बताएं)

ख) सकल भर्ती अनुपात (जीईआर) (पिछले तीन वर्षों में)

भर्ती	वर्ष	कुल		एसटी	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
प्राथमिक स्कूल भर्तियाँ					
उच्च प्राथमिक भर्तियाँ					

12. शिक्षक-छात्र अनुपात और शिक्षकों की रिक्ति प्रतिशतता

क्र. सं.	विषय	विद्यालय स्तर	सभी स्कूलों के लिए राज्य-स्तरीय आंकड़े		एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल (ईएमआरएस के अलावा), जैसे आश्रम स्कूल आदि।
			कुल	एसटी		
क.	शिक्षक – विद्यार्थी अनुपात	प्राथमिक				
		माध्यमिक				
		सेकण्डरी				
ख.	शिक्षक रिक्ति पद	प्राथमिक				
		माध्यमिक				
		सेकण्डरी				
ग.	औसत ड्रॉप-आउट दर (बालक)	प्राथमिक				
		माध्यमिक				
		सेकण्डरी				
घ.	औसत ड्रॉप-आउट दर (बालिकाएं)	प्राथमिक				
		माध्यमिक				
		सेकण्डरी				
ङ.	उत्तीर्णता प्रतिशत (बालक)	प्राथमिक				
		माध्यमिक				
		सेकण्डरी				
च.	उत्तीर्णता प्रतिशत (बालिकाएं)	प्राथमिक				
		माध्यमिक				
		सेकण्डरी				

13. व्यावसायिक संस्थान (केन्द्रीय/राष्ट्रीय के अलावा) में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें

वर्ष (पिछले तीन वर्षों में)	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या		अनुसूचित जनजातियों द्वारा भरी गई सीटों की संख्या		वर्ष के अंत में आयोजित अंतिम परीक्षा में उत्तीर्णता प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति के संबंध में)	
	पेशेवर	अन्य	पेशेवर	अन्य	पेशेवर	अन्य

14. कोचिंग और प्रशिक्षण:

क. विशेष कोचिंग / ब्रिज पाठ्यक्रम (प्रतियोगी परीक्षाएँ, विद्यालयी विषय, व्यावसायिक प्रशिक्षण)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	कोचिंग / प्रशिक्षण का प्रकार (प्रतियोगी परीक्षाएँ / ब्रिज पाठ्यक्रम / व्यावसायिक)	भर्ती एसटी विद्यार्थियों की कुल संख्या	पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले एसटी विद्यार्थियों की कुल संख्या	प्राप्त नौकरियाँ/परिणाम	टिप्पणी/चुनौतियाँ
1						
2						
3						

ख. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु विशेष कोचिंग कार्यक्रमों की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्यान्वयन का वर्ष	भर्ती विद्यार्थी की कुल संख्या	लाभ/ नौकरियाँ प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	टिप्पणी
1					
2					
3					

छ. जनजातीय / सामाजिक कल्याण

15. राज्य सरकार द्वारा प्रचालित छात्रावास (आज तक)

i. कार्यशील जनजातीय छात्रावासों की संख्या तथा उनकी स्वीकृत भर्ती क्षमता और रिक्त सीटें -

प्रकार	छात्रावास की संख्या		भर्ती क्षमता		रिक्त सीटें	
	लड़के	लड़कियाँ	लड़के	लड़कियाँ	लड़के	लड़कियाँ
मैट्रिक-पूर्व						
मैट्रिक-पश्चात						

ii. मूलभूत अवसंरचना-

विवरण	छात्रावास वार्डन के बिना	छात्रावास अधीक्षक के बिना	सुरक्षा कर्मियों के बिना	सीसीटीवी कैमरा के बिना
छात्रावास की संख्या				

iii. राज्य में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) का विवरण-

क्र. सं.	जिला/स्थान	ईएमआरएस की संख्या				स्वीकृत विद्यार्थियों की संख्या (क्षमता)		भर्ती विद्यार्थियों की संख्या	
		स्वीकृत	कार्यात्मक	निर्माणाधीन	अन्य भवनों में संचालित	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं

क. मेस के बिना ईएमआरएस विद्यालयों की संख्या

ख. वार्डन के बिना ईएमआरएस विद्यालयों की संख्या

ग. खेलकूद सहित ईएमआरएस द्वारा प्राप्त कोई विशेष उपलब्धि -

16. छात्रवृत्ति (पिछले तीन वर्षों में)

प्रकार	योजना/ संकेतक	पिछले 3 वित्तीय वर्ष (संख्या और प्रतिशत)		
		वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति लाभार्थी	कुल लाभार्थी			
	अनुसूचित जनजाति लाभार्थी			
मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति लाभार्थी	कुल लाभार्थी			
	अनुसूचित जनजाति लाभार्थी			
राज्य द्वारा संचालित मेधा छात्रवृत्ति, यदि कोई हो"	कुल लाभार्थी			
	अनुसूचित जनजाति लाभार्थी			

ज. कौशल विकास और रोजगार

क. कौशल

i. प्रशिक्षण विवरण- (पिछले 3 वर्षों के लिए)

प्रशिक्षित उम्मीदवार	वर्ष	कुल		अनुसूचित जनजाति	
		प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त*	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त *
क. पीएमकेवीवाई/स्किल इंडिया					
ख. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)/ आरयूडीएसईटी					
		प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त*	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त *
ग. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)					
घ. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)					

प्रशिक्षित उम्मीदवार	वर्ष	कुल	अनुसूचित जनजाति
ड. पॉलिटैक्निक संस्थान			

* उद्यमियों सहित नौकरी प्राप्त करने वाले उम्मीदवार

क. पीएमकेवीवाई/स्किल इंडिया पहल के अंतर्गत संचालित प्रमुख व्यवसाय/पाठ्यक्रम (उदाहरणार्थ: शीर्ष 10)-

ii. छात्र/कर्मचारी स्थिति

विद्यार्थी							
संस्थान का प्रकार	सरकारी संस्थान की संख्या	स्वीकृत सीट		भरी हुई सीटें		रिक्त सीटें	
		कुल	एसटी	कुल	एसटी	कुल	एसटी
आईटीआई							
पॉलिटैक्निक							

शिक्षक/कर्मचारी							
संस्थान का प्रकार	सरकारी संस्थान की संख्या	स्वीकृत सीट		भरी हुई सीटें		रिक्त सीटें	
		कुल	एसटी	कुल	एसटी	कुल	एसटी
आईटीआई							
पॉलिटैक्निक							

ख. रोजगार

iii. नौकरी के इच्छुक (पिछले तीन वर्षों में)-

विवरण		वर्ष	कुल	एसटी
राज्य सरकार के पोर्टल/रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नौकरी के इच्छुक व्यक्ति				
सभी रोजगार कार्यालयों/पोर्टल के माध्यम से प्राप्त नौकरियाँ				

ग. प्रवासन आंकड़ें-

क. कुल प्रवासन-

ख. अनुसूचित जनजाति प्रवासन-

झ. वन अधिकार एवं संबंधित जानकारी

17. अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006/वन अधिकार अधिनियम (एफ़आरए)-

i. कुल अभिज्ञात वन भूमि (एकड़ में):

ii. क्या राज्य में कोई वन ग्राम है? (यदि हाँ), वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में परिवर्तन की स्थिति क्या है?

iii. पिछले तीन वर्षों में वितरित एफ़आरए पट्टे (वर्षवार):

वितरित पट्टे	वर्ष	प्राप्त कुल	स्वीकृत पट्टे	वितरित पट्टे	अस्वीकृत	लंबित पट्टा दावे

		दावे			पट्टा दावे पट्टा पट्टा दावे	ग्राम सभा	ब्लॉक	जिला
व्यक्तिगत वन अधिकार								
सामुदायिक वन अधिकार								
सामुदायिक वन संसाधन								

- iv. प्रति लाभार्थी आवंटित भूमि का औसत क्षेत्रफल (एकड़ में):
- v. क्या विभिन्न स्तरों पर अस्वीकृत दावों के संबंध में कोई समीक्षा की गई है, यदि हां तो उसमें क्या प्रगति हुई है?
- vi. राज्य में वन्यजीव अभयारण्यों/बाघ अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों/चिड़ियाघर परियोजनाओं की संख्या -
क. कृपया कोर क्षेत्र एवं बफर ज़ोन में स्थित उन ग्रामों एवं परिवारों की संख्या का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें, जिन्हें स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा मुआवज़े की स्थिति का विवरण भी प्रदान करें।

ग) लघु वन उपज

- i. क्या राज्य में अनुसूचित जनजातियों द्वारा कोई लघु वनोपज (एमएफपी) एकत्रित की जाती है? यदि हाँ, तो ऐसी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?
- ii. लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का विवरण:
- iii. राज्य में वनधन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की संख्या:
क. जिलावार वीडवीके का विवरण -
- iv. क्या एमएफपी के विपणन के लिए किसी एनजीओ/एजेंसी को पैनाल में शामिल किया गया है?:

घ. कृषि

- i. समग्र जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की कुल कृषि भूमि जोतों का विवरण
- ii. कृषि पर निर्भर अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों की कुल संख्या।-
- iii. भूमिहीन अनुसूचित जनजाति परिवारों की कुल संख्या -
- iv. राज्य प्रशासन द्वारा कार्यान्वित की जा रही कृषि आदान योजना का विवरण; योजना का नाम, प्रदान की गई सहायता का प्रकार, तथा कवरेज की सीमा का विवरण प्रस्तुत करें।
क. कुल:
ख. अनुसूचित जनजाति:
- v. पीएम-किसान निधि योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या -

वर्ष	कुल लाभार्थी (सभी)	कुल लाभार्थी (अनुसूचित जनजाति)	कुल लाभार्थियों में से अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों का प्रतिशत	कुल वितरित राशि (लाख ₹ में)	अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को वितरित राशि (लाख ₹ में)	टिप्पणी

vi. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएम-एफबीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या -

वर्ष	कुल लाभार्थी (सभी)	कुल लाभार्थी (अनुसूचित जनजाति)	कुल लाभार्थियों अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों का प्रतिशत	कुल वितरित राशि (लाख ₹ में)	अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को वितरित राशि (लाख ₹में)	टिप्पणी

vii. क्या राज्य में स्थानान्तरित कृषि (स्लेश एंड बर्न) की प्रथा है? यदि हाँ,
 क. स्थानान्तरित कृषि के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
 ख. इस प्रकार कृषि करने वाले परिवारों की संख्या
 ग. किए गए विशिष्ट उपाय (योजनाएँ/कार्यक्रम/मध्यवर्तन)

viii. राज्य में जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)-

वर्ष	पात्र किसानों की कुल संख्या	कुल वितरित एसएचसी	पात्र अनुसूचित जनजाति किसानों की कुल संख्या	अनुसूचित जनजाति को वितरित एसएचसी	प्रतिशत कवरेज (कुल)	प्रतिशत कवरेज (अनुसूचित जनजाति किसान)

ix. राज्य में किसान उत्पादक संगठन (एफ़पीओ)-

क. कुल और कार्यात्मक-

ख. विशेष रूप से एसटी समुदाय के लिए कोई एफ़पीओ-

x. राज्य में कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की संख्या-

क. वरिष्ठ वैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों की संख्या-

xi. राज्य में पशु चिकित्सालयों की संख्या-

xii. राज्य में चारागाहों की जानकारी-

ड) सिंचाई

i. राज्य में सिंचित और असिंचित जमीन की जोत (एकड़ में) (पिछले तीन साल में)

वर्ष	कुल भूमि जोत (कुल)	सिंचित भूमि (कुल)	सिंचित भूमि (एसटी)	असिंचित भूमि (कुल)	असिंचित भूमि (एसटी)	% सिंचित (कुल)	% सिंचित (एसटी)	टिप्पणी

ii. क्या राज्य में किसानों के लिए सिंचाई की कोई योजना है (जैसे मध्य प्रदेश राज्य में कपिल धारा योजना), यदि हाँ, तो उसकी जानकारी प्रदान करें-

च) पशुपालन

योजना का नाम	वर्ष	कुल लाभार्थी	एसटी लाभार्थी	अनुसूचित जनजाति	टिप्पणी

				लाभार्थियों का प्रतिशत	
राष्ट्रीय गोकुल मिशन					
राज्य पशुपालन योजना					
अन्य योजना (योजनाएं) (विवरण प्रदान करें)					

छ) मत्स्य पालन

- i. मछुआरा सहकारी समितियों की कुल संख्या
 - क. कुल:
 - ख. अनुसूचित जनजाति:
- ii. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या
 - क. कुल:
 - ख. अनुसूचित जनजाति:

ज. वित्तीय समावेशन और आजीविका

18. बैंकिंग

- i. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की पिछली तीन बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतियाँ -
- ii. जन धन खाता (पिछले तीन वर्ष में)-

वर्ष	कुल खाता (लाखों में)		शेष राशि (करोड़ में)		शून्य शेष वाले खातों की संख्या (लाखों में)		शून्य शेष खातों का %		जारी किए गए रूपये कार्ड (लाखों में)	
	कुल	एसटी	कुल	एसटी	कुल	एसटी	कुल	एसटी	कुल	एसटी

19. क्रेडिट

- i. निम्न के माध्यम से ऋण प्राप्ति का ब्यौरा -
 - क. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)-
 - ख. राज्य वित्त एवं विकास निगम (यदि लागू हो)
 - ग. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)-
- ii. स्टैंड अप/स्टार्टअप इंडिया के तहत लाभार्थी (पिछले तीन वर्ष में)-

वर्ष	योजना (स्टैंड अप इंडिया/ स्टार्टअप इंडिया)	कुल लाभार्थी	एसटी लाभार्थी	स्वीकृत राशि (लाख ₹में)	वितरित राशि (लाख ₹में)

iii. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत जानकारी: (2 वर्ष और चालू वर्ष)

विवरण	शिशु		किशोर		तरुण		तरुण प्लस	
	कुल	एसटी	कुल	एसटी	कुल	एसटी	कुल	एसटी
प्राप्त आवेदनों की संख्या								
स्वीकृत आवेदनों की संख्या								
अस्वीकृत आवेदनों की संख्या								
लाभार्थियों की संख्या और वितरित राशि								
कुल वितरित निधि (₹ में)								

iv. पीएम स्वनिधि -

क. पीएम स्वनिधि के तहत वितरित प्रमाणपत्र

पीएम स्वनिधि योजना	प्राप्त आवेदनों की संख्या		नगर निगम		नगर परिषद		नगर पालिका	
	कुल	एसटी	कुल	एसटी	कुल	एसटी	कुल	एसटी
लाभार्थी की संख्या								
वितरित निधि								

v. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) का औपचारिकीकरण योजना -

पीएमएफएमई योजना	जमा किया गए आवेदन		स्वीकृत ऋण		वितरित ऋण	
	कुल	एसटी	कुल	एसटी	कुल	एसटी
लाभार्थी की संख्या						
वितरित निधि						

20. आजीविका (आज की स्थिति के अनुसार)

- कुल गठित/सहायता प्राप्त महिला स्वयं सहायता समूह -
- स्वयं सहायता समूहों के लिए समग्र परिक्रामी निधि (लाख ₹ में)-
- लखपति दीदियों की संख्या -
 - कुल
 - एसटी
- नमो ड्रोन दीदी की संख्या-
 - कुल
 - एसटी
- विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका की गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी) (इससे पूर्व- एमजीएनआरईजीए)- (पिछले तीन वर्षों में)

संकेतक	कुल	एसटी
सक्रिय जॉब कार्ड धारकों की कुल संख्या (आज की स्थिति के अनुसार)		

संकेतक	कुल	एसटी
कुल नियोजित व्यक्ति-दिन		
नियोजित महिला लाभार्थियों की संख्या (आज की स्थिति के अनुसार)		
वर्तमान मजदूरी दर (रु.)		
अतिरिक्त 50 दिन, कुल मिलाकर 150 दिन का रोजगार पूरे करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान),	-	
(पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान) कुल संवितरण रुपये में		

ट. आवास और अवसंरचना

21. प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

वर्ष	स्वीकृत घरों/आवास स्थलों की कुल संख्या		निर्माणाधीन घरों/आवास स्थलों की कुल संख्या		निर्मित घरों/आवास स्थलों की कुल संख्या	
	कुल	एसटी	कुल	एसटी	कुल	एसटी

- i. राज्य की आवासन योजनाओं का विवरण भी उपलब्ध कराएं, यदि कोई हो।

22. जल आपूर्ति

- i. नल से पेयजल जल जीवन मिशन (एफ़एचटीसी) सुविधा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या तथा जनजातीय बस्तियों में उपलब्ध कराए गए सामुदायिक जल स्रोतों का विवरण प्रस्तुत करें।

वर्ष	स्वीकृत घरों/आवास स्थलों की कुल संख्या		निर्माणाधीन घरों/आवास स्थलों की कुल संख्या		निर्मित घरों/आवास स्थलों की कुल संख्या	
	कुल	एसटी	कुल	एसटी	कुल	एसटी

23. स्वच्छता

- i. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण/शहरी) के अंतर्गत निर्मित व्यक्तिगत शौचालयों वाले परिवारों की संख्या
- क. कुल-
- ख. एसटी
- ii. व्यक्तिगत शौचालय से वंचित/अभी तक शौचालय प्राप्त न करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या

24. सड़कें (पीएमजीएसवाई)

- अनुसूचित जनजाति बस्तियों (पीएमजीएसवाई) को जोड़ने वाली निर्मित ग्रामीण सड़कों की किलोमीटर में गणना तथा पक्की सड़क से जोड़े गए इससे पहले असंबद्ध जनजातीय गांवों की संख्या बताइए।
- पक्की सड़क के संपर्क से वंचित बस्तियों की संख्या -
 - कुल
 - एसटी
- राज्य में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों की कुल लंबाई (किलोमीटर में) -

ठ. अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षा उपाय, सेवा मामले और कानूनी तंत्र

25. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989/पीओए अधिनियम, 1989

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत पंजीकृत-मामलों की जानकारी (पिछले तीन वर्ष में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष - 1	वर्ष - 2	वर्ष - 3
क.	वर्ष की शुरुआत में सुनवाई के लिए मामले (एसटी)			
ख.	वर्ष के दौरान सुनवाई के लिए भेजे गए मामले (एसटी)			
ग.	सुनवाई के लिए कुल मामले (क + ख) (एसटी)			
घ.	मामले जिनमें आरोप तय किए गए (एसटी)			
ङ.	मामले जिनमें दोषसिद्ध हुआ (एसटी)			
च.	दोषमुक्ति/डिस्चार्ज (एसटी) के मामले			
छ.	वापस लिए गए /कंपाउंड किए गए (एसटी) मामले, अगर कोई हों			
ज.	वर्ष के आखिर में लंबित मामले (एसटी)			

- क्या सभी जिलों में पीओए एक्ट के तहत पंजीकृत मामलों को देखने के लिए कोई खास विशेष न्यायालय बनाया गया है? क्या विशेष अभियोक्ता नियुक्त किए गए हैं? अगर हाँ, तो उसका विवरण बताएँ।
- क्या एससी/एसटी पीओए नियम 1995 की धारा 16 के तहत राज्य स्तरीय जागरूकता और निगरानी समितियाँ (एसएलवीएमसी) बनाई गई हैं?
 - यदि हाँ, तो कृपया पिछली तीन बैठकों के कार्यवृत्त साझा करें।
- क्या एससी/एसटी पीओए नियम 1995 की धारा 17क के तहत जिला स्तरीय जागरूकता और निगरानी समितियाँ (डीएलवीएमसी) बनाई गई हैं?
 - यदि हाँ, तो आयोजित बैठकों की संख्या की जानकारी दें।

- v. क्या एससी/एसटी पीओए नियम 1995 के धारा 17क के तहत सब-डिविजनल स्तरीय जागरूकता और निगरानी समितियाँ (एसडीएलवीएमसी) बनाई गई हैं? यदि नहीं, तो कृपया इसके न बनने का कारण बताएं।
- vi. राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के क्रमांक 46 के अनुरूप नियम 12(4) के अंतर्गत प्रदत्त पेंशन लाभों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरण प्रस्तुत करें।
- vii. कृपया एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम 1989 के तहत पीड़ितों को दिए गए मुआवजे और मुआवजे की संवितरण हेतु देय किस्त (पिछले 3 वर्ष में) पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें:

प्रकार	वर्ष	एफ़आईआर स्तर पर		आरोपपत्र दायर करने के स्तर पर		दोषसिद्धि पर	
		कुल मामलों	संवितरण किया गया	मामले	संवितरण किया गया	मामले	संवितरण किया गया
पीड़ितों की संख्या							
वितरित राशि							

- viii. जेल में बंद लोगों की स्थिति (अनुसूचित जनजातियाँ)
 - क. कुल कैदी
 - ख. अनुसूचित जनजाति (एसटी) कैदी
 - ग. एसटी कैदियों का प्रतिशत (%)
- ix. राज्य में एससी/एसटी के लिए खास पुलिस स्टेशनों की संख्या (जिलावार)

26. पंचायती राज संस्था से संबंधित*

(*केवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान राज्यों के लिए जिनके जनजातीय क्षेत्र पाँचवी अनुसूची के तहत घोषित किए गए हैं)

क. स्थानीय स्वशासन

- i. क्या राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में जिला, ब्लॉक और गाँव स्तर पर स्थानीय स्वशासन स्थापित किए हैं? यदि हाँ, तो किस अधिनियम के तहत? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?
- ii. इन स्थानीय निकायों के लिए चुनाव पिछली बार कब हुए थे?
- iii. कृपया बताएं कि ये स्थानीय निकाय अभी काम कर रहे हैं। यदि नहीं, तो इसका कारण बताएं।
- iv. स्थानीय निकायों को प्रदत्त शक्तियों, कार्यों और विषयों का विवरण दें।
- v. कृपया बताएं कि क्या इन स्थानीय निकायों को कोई वित्तीय शक्तियाँ दी गई है।
- vi. कृपया पिछले तीन वर्षों में स्थानीय निकायों को जारी की गई निधि की राशि और वह तारीख/महीना बताएं जब निधि जारी की गई थी?

ख. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पेसा)

- i. क्या राज्य सरकार ने पेसा नियम बनाए हैं? यदि हाँ, तो कृपया नीचे दी गई जानकारी दें। यदि नहीं, तो इसका कारण बताएं।
 - क. कृपया राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या और राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में उनकी संख्या के बारे में जिलेवार जानकारी दें।
 - ख. पेसा नियमों के तहत उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या तंत्र है?

- ग. पेसा नियमों के अनुसार, प्रत्येक ग्राम सभा दो माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी। कृपया बताएं कि क्या कुछ ग्राम सभाएं समय-समय पर बैठक नहीं कर रही हैं, और यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति के क्या कारण हैं? क्या ऐसी कोई घटनाएं हुई है जहां कोरम पूरा न होने के कारण बैठक नहीं हो सकी।
- घ. कृपया अनुसूचित क्षेत्रों में उन ग्राम सभाओं की जानकारी दें, जिनके अध्यक्ष के रूप में कोई एसटी व्यक्ति नहीं है।
- ङ. कृपया अनुसूचित क्षेत्रों में उन ग्राम सभाओं की जानकारी दें जिनकी अध्यक्ष एसटी महिला हैं।
- ii. कृपया जानकारी दें कि क्या गाँव के कामकाज के अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, जनजातीय क्षेत्र की सभी ग्राम सभाओं ने ऐसी समितियाँ बनाई हैं:
- शांति समिति,
 - न्याय समिति,
 - संसाधन योजना और प्रबंधन समिति,
 - नशा नियंत्रण समिति,
 - ऋण नियंत्रण समिति,
 - बाजार समिति,
 - सभा कोष समिति और
 - अन्य समितियाँ जिन्हें ग्राम सभा द्वारा उचित समझा जाए
- iii. कृपया ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी भी सरकारी विभाग द्वारा बनाए गए निकायों या समितियों की जानकारी दें और बताएं कि क्या ऐसी समितियाँ संबंधित ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेह हैं।
- iv. कृपया ग्राम सभा कोष के संसाधनों और उस कोष के उपभोग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें।
- v. ग्राम सभा द्वारा विवाद समाधान की प्रक्रिया क्या है?
- vi. कृपया बताएं कि ग्राम सभा यह कैसे पक्का करती है कि संसाधनों का उपयोग हो।
- vii. कृपया अनुसूचित जनजातियों की जमीन को गैर-एसटी लोगों के नाम पर स्थानांतरित करने के बारे में मिले मामलों और ग्राम सभा द्वारा निर्णित मामलों की जानकारी दें।
- viii. कृपया उन घटनाओं की जानकारी दें जिनमें ग्राम सभाओं ने यह राय दी है कि कोई राज्य कानून, रीति रिवाजों, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन के तरीकों के संगत नहीं है, और यदि ऐसा है तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दें।

27. सेवा सुरक्षा उपाय

- i. राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न सेवाओं में आरक्षण का कोटा क्या है
 - a. सीधी भर्ती में:
 - b. पदोन्नति में:
- ii. सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को क्या रियायतें/छूट दी जा रही हैं?
- iii. अनुसूचित जनजाति अधिकारियों को पदोन्नति में क्या रियायतें/छूट दी जा रही हैं?
- iv. कुल कर्मचारियों का विवरण -

	कुल		एसटी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
कुल कर्मचारी				

- v. अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में आरक्षण समाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है?
- vi. पिछले तीन वर्षों में रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए कितनी संख्या में प्रस्ताव किए गए तथा आरक्षण समाप्त करने के लिए कितनी संख्या पर सहमति बनी है?
- vii. आरक्षण समाप्त करने के सामान्य/सबसे सामान्य आधार क्या थे?

- viii. क्या यह तथ्य नहीं है कि आरक्षण समाप्त करने की मांग का मुख्य कारण अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों में बड़े पैमाने पर कमी/बैकलॉग, ग्रुप बी, सी और डी स्तर पर फीडर ग्रेड पदों को भरने में ढिलाई है?
- ix. विभिन्न स्तरों पर एसटी कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए क्या तंत्र बनाए गए हैं?
- x. कृपया राज्य सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में भी इसी प्रकार की जानकारी प्रदान की जाए।

तालिका 1: राज्य सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

पद का समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	एसटी कर्मचारियों की कुल संख्या		कुल कर्मचारियों में एसटी का प्रतिशत		टिप्पणी
		अपनी योग्यता के आधार पर	आरक्षण के आधार पर	अपनी योग्यता के आधार पर	आरक्षण के आधार पर	
ग्रुप ए (ग्रुप ए के सबसे निचले पायदान को छोड़कर)/समकक्ष						
ग्रुप ए (ग्रुप ए का सबसे निचला पायदान)/समकक्ष						
ग्रुप बी/समकक्ष						
ग्रुप सी						
ग्रुप डी (सफाई कर्मचारियों के अलावा)						
सफाई कर्मचारी						

तालिका 2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

पद का समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	एसटी कर्मचारियों की संख्या		कुल कर्मचारियों में एसटी का प्रतिशत		टिप्पणी
		अपनी योग्यता के आधार पर	आरक्षण के आधार पर	अपनी योग्यता के आधार पर	आरक्षण के आधार पर	
ग्रुप ए (ग्रुप ए के सबसे निचले पायदान को छोड़कर)/समकक्ष						
ग्रुप ए (ग्रुप ए का सबसे निचला पायदान)/समकक्ष						
ग्रुप बी/समकक्ष						
ग्रुप सी						
ग्रुप डी (सफाई कर्मचारियों के अलावा)						
सफाई कर्मचारी						

- xi. क्या राज्य ने सेवाओं/पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को नियंत्रित करने वाला कोई अधिनियम लागू किया है? यदि हाँ, तो अधिनियम की एक प्रति, किए गए संशोधनों की अद्यतन सूची और अन्य संबंधित निर्देशों/आदेशों सहित, उपलब्ध कराई जाए?

i. अनुसूचित जनजातियों के जाति प्रमाण पत्र/ वास्तविक दावों का सत्यापन

उप-घटक / योजना	वर्ष	जारी किए गए कुल अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र	सत्यापन के लिए प्राप्त हुए फर्जी एसटी प्रमाणपत्र
फर्जी एसटी जाति प्रमाण पत्र	वर्तमान वर्ष		
	पिछले वर्ष		

- i. क्या जिलों/प्रभागों/राज्य में कोई जांच समिति गठित की गई है? यदि हाँ, तो कृपया इसके गठन की तिथि और पिछली तीन बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतियाँ प्रदान करें। यदि नहीं, तो कृपया इसका गठन न होने के कारण स्पष्ट करें।
- ii. क्या अनुसूचित जनजाति (एसटी) जाति प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जारी करने का कोई प्रावधान है, या यह प्रक्रिया अभी भी मैनुअल है?
क. राज्य में जारी किए गए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की वैधता क्या है?
- iii. एसटी के लिए किए गए आरक्षण वास्तव में लागू हों, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या जांच प्रक्रिया बनाई गई है?
क. क्या ऐसे मामले हैं जहाँ लोगों ने झूठे एसटी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर राज्य सरकार के तहत नौकरी हासिल की है?
ख. यदि हाँ, तो राज्य सरकार के ध्यान में लाए गए ऐसे मामलों की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी दें।
ग. ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताएं।

शिक्षा के लिए

- i. कृपया पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों में भर्ती के समय जांच किए गए दावों की संख्या और वास्तव में झूठे/नकली पाए गए दावों की सूची और प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई प्रस्तुत करें।
- ii. कृपया पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों में उन विद्यार्थियों की जानकारी दें जिनके खिलाफ झूठे/फर्जी/धोखाधड़ी के आधार पर या अयोग्य अभ्यर्थी के तौर पर एसटी अभ्यर्थी की सीट पर भर्ती लेने की शिकायतें मिली थीं, प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई (जांच) और शिकायत सही पाए जाने पर सक्षम अधिकारी/अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा मामले का निपटान/लिया गया निर्णय का विवरण प्रस्तुत करें।
- iii. कृपया बताएं कि क्या राज्य सरकार ने वर्ष 1994 के मशहूर माधुरी पाटिल केस में जारी किए गए फर्जी/धोखे से प्राप्त किए गए जाति प्रमाणपत्र या अमान्य जाति प्रमाणपत्रों/ दूसरे राज्य के प्रमाण पत्रों के आधार पर अयोग्य उम्मीदवारों द्वारा अनुसूचित जनजाति के तौर पर किए गए झूठे दावों के मामलों को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए कोई कानून/नियम बनाया है।

नौकरीपेशा लोगों के लिए

- i. कृपया भर्ती के समय जांच किए गए दावों की संख्या और वास्तव में झूठे/नकली पाए गए दावों की सूची प्रस्तुत करें, और पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई का विवरण दें।
- ii. कृपया पदोन्नति के समय झूठे/फर्जी पाए गए दावों की सूची और पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई का विवरण भी दें।
- iii. कृपया उन मामलों की सूची दें जिनमें पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में एसटी अभ्यर्थी को एसटी सूची से उनके समुदाय का नाम हटाने की वजह से एसटी अभ्यर्थी के तौर पर पदोन्नति के लिए अयोग्य पाया गया।

- iv. कृपया उन कर्मचारियों की जानकारी दें जिनके खिलाफ पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में एसटी अभ्यर्थी के तौर पर झूठे/फर्जी/धोखाधड़ी के आधार पर नौकरी पाने की शिकायतें मिली थीं, प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई (जांच) और शिकायत के मामले में सक्षम अधिकारी/अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा किए गए निपटान/ निर्णय का विवरण दें।

ड. शासन और कार्यान्वयन तंत्र

28. जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी):

- i. क्या टीएसी का गठन किया गया है (जहाँ भी अधिदेशित है।) कृपया इसके नवीनतम गठन की तारीख, बैठकों की संख्या और बैठकों की तारीखों का विवरण और पिछले तीन वर्षों के कार्यवृत्त की प्रति प्रदान करें।

29. प्रमुख परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण/भूमि आवंटन एवं भूमि से बेदखली

क) भूमि आवंटन और भूमि से बेदखली (पिछले तीन वर्षों में)

- i. कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीब अनुसूचित जनजातियों को आवंटित सिंचित या असिंचित भूमि का आकार-वार विवरण प्रस्तुत करें।

वर्ष	भूमि आकार श्रेणी (एकड़/हेक्टेयर में)	आवंटित सिंचित भूमि (एकड़/हेक्टेयर)	आवंटित गैर-सिंचित भूमि (एकड़/हेक्टेयर)	कुल लाभार्थी (एसटी)

- ii. अनुसूचित जनजातियों की भूमि के बेदखली को रोकने के लिए क्या विधायी और प्रबंधकीय उपाय किए गए हैं?
- iii. पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भूमि से बेदखली के कितने मामले सामने आए हैं?
- iv. अब तक कितने मामलों का निपटान किया जा चुका है?

30. प्रमुख परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

- i. विकास प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति में लोगों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार की क्या नीति है?
- ii. कृपया उन प्रमुख परियोजनाओं जिनके लिए पिछले पांच वर्षों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की गई, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का कुल आकार, प्रभावित कुल और अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या तथा अधिग्रहण के कारण वास्तव में विस्थापित हुए लोगों की संख्या, स्वीकृत या प्रस्तावित मुआवजा तथा प्रत्येक परिवार को स्वीकृत और वास्तव में प्रदान की गई पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रक्रिया का ब्यौरा प्रस्तुत करें।

परियोजना का नाम	भूमि अधिग्रहण की शुरुआत करने का वर्ष	कुल अधिग्रहित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर/एकड़ में)	कुल प्रभावित परिवार	प्रभावित अनुसूचित जनजाति परिवार	वास्तव में विस्थापित हुए परिवार	स्वीकृत/प्रस्तावित मुआवजा (₹)

- iii. कृपया ब्यौरा दें कि क्या भूमि अधिग्रहण से संबंधित कुछ मुद्दे अभी भी लंबित हैं और परियोजना से प्रभावित व्यक्ति अधिग्रहण के विरुद्ध या मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के स्तर के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं?

31. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338क का खंड (9)

- i. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (9) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाली योजनाओं के संबंध में एनसीएसटी के साथ राज्य द्वारा किए गए परामर्श का विवरण।

32. राज्य में जनजातीय अनुसंधान संस्थान

- i. पिछले 5 सालों में जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययनों का विवरण।

ढ. छठी अनुसूची क्षेत्र के राज्य से जानकारी

33. जिला परिषदें और क्षेत्रीय परिषदें

- i. जिला परिषदें/क्षेत्रीय परिषदों का प्रशासनिक ढांचा:
 - क. जिला परिषदें/क्षेत्रीय परिषदों की संख्या-
 - ख. परिषदों को दी गई शक्तियों (विधायी, कार्यकारी, न्यायिक, वित्तीय)
 - ग. प्रत्येक जिला परिषद/क्षेत्रीय परिषद के तहत स्थानांतरित किए गए विषयों और आरक्षित विषयों की जानकारी की सूची प्रदान करें-
- ii. शक्तियों का हस्तांतरण:
 - क. क्या छठी अनुसूची के तहत सभी अधिकार पूरी तरह से एडीसी को सौंप दिए गए हैं?
 - ख. क्या राज्य सरकार और एडीसी के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई विवाद है?
- iii. प्रत्येक जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद में सदस्यों की जानकारी दें-
- iv. उन विषयों की सूची प्रदान करें जिन पर प्रत्येक जिला/क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने का अधिकार है (छठी अनुसूची का पैरा 3)-
 - क. उपर्युक्त खण्ड के तहत बनाए गए अधिनियम, नियम और कानून का विवरण-
 - ख. उपर्युक्त विषय के अलावा नियम बनाने की कोई अतिरिक्त शक्ति-
- v. जिला और क्षेत्रीय निधियों (लाखों में) का विवरण (पिछले तीन वर्षों में)-

वित्तीय वर्ष	विभाग	आवंटन	जारी	व्यय	टिप्पणी

- vi. भू-राजस्व का आकलन और संग्रहण करने तथा कर लगाने की शक्तियों का विवरण-
- vii. परिषद के राजस्व का स्रोत (लाखों में) (पिछले तीन वर्षों में)-

वित्तीय वर्ष	स्रोत	आय	व्यय	टिप्पणी

- viii. गैर-जनजातीय लोगों द्वारा साहूकारी और व्यापार पर नियंत्रण के लिए विनियमों का विवरण-
- ix. परिषद द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और विनियमों के प्रकाशन की एक प्रति प्रदान करें -
- x. क्या स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के प्रशासन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए राज्यपाल द्वारा कोई आयोग बनाया गया है, यदि हाँ, तो उसकी जानकारी प्रदान करें।

क. स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के प्रशासन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग की नियुक्तियों की संख्या (छठी अनुसूची की पैरा 14), और उसकी रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करें-

- xi. कोई अधिनियम या प्रस्ताव जो जिला और क्षेत्रीय परिषदों के निर्धारित प्रस्तावों के निरस्तीकरण या निलंबन के अधीन था।
- xii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1)के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुदानों के अंतर्गत स्वीकृत और कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की प्रकृति	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत वित्तीय व्यय (लाख रूपये में)	कार्यान्वयन एजेंसी	वास्तविक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	वर्तमान स्थिति (प्रगति पर /पूर्ण/ शुरू नहीं हुआ)	टिप्पणी

- xiii. राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे गए नियमों की स्थिति — जिसमें निम्नलिखित शामिल हो-
- क. मंजूरी के लिए भेजे गए नियमों की कुल संख्या,
- ख. राज्यपाल द्वारा स्वीकृत नियमों की संख्या, और
- ग. मंजूरी के लिए लंबित नियमों की संख्या, यदि कोई है।
